

देश-देशांतर/सकियूरटी स्कैन: अमेरिका-ईरान वविद और भारत की चतिाँ

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बहुपक्षीय परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग करने की घोषणा करते हुए ईरान पर फरि से आर्थिक प्रतर्बिध लागू कर दधि हैं। समझौते से अमेरिका के हटने की घोषणा के कुछ देर बाद ही उन्होंने ईरान के खलिाफ ताजा प्रतर्बिधों वाले दस्तावेजों पर हस्ताकषर कर दधि तथा अन्य देशों को ईरान के वविदति परमाणु हथियार कार्यक्रम पर उसके साथ सहयोग करने के खलिाफ चेतावनी भी दी। वगित लगभग तीन माह से अमेरिका और ईरान के बीच इस डील को लेकर कशमकश चल रही थी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने पाँच अन्य महाशक्तियों के साथ मलिकर ईरान के साथ तीन साल पहले 14 जुलाई, 2015 को परमाणु समझौता कधि था। **संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना** (Joint Comprehensive Plan Of Action-JCPOA) को ही 'परमाणु डील' के नाम से जाना जाता है।

यहाँ इस समझौते के एक तकनीकी बदि को समझ लेना भी आवश्यक है, जसमें कहा गया है कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रत्येक चार महीने में इस समझौते की समीक्षा कर इसे जारी रखने या न रखने का नरिणय लेंगे। इसी वर्ष जनवरी में जब यह समझौता डोनाल्ड ट्रंप के पास समीक्षा के लधि आया था, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगली बार (मई 2018) जब यह मेरे सामने आएगा तो मैं बारीकी से इसकी समीक्षा करने के बाद ही कोई नरिणय लूँगा।

समझौते से हटने के पीछे अमेरिका का तरक

अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से हटने का ऐलान तय समय से तीन दनि पहले ही कर दधि। उन्होंने कहा, "हम ईरान को परमाणु बम बनाने से नहीं रोक सकते। यह समझौता भीतर से ही दोषपूर्ण है। इस वनिाशकारी समझौते ने ईरान को करोड़ों डॉलर दधि, लेकिन उसे परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक सके। परमाणु डील बराक ओबामा प्रशासन में की गई सबसे बड़ी और ऐतहासिक भूल थी। इससे देश और दुनधि को कोई फायदा नहीं पहुँचा, बल्कि इसकी आड़ में ईरान लगातार दुनधि की आँखों में धूल झोंकता रहा और अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखता रहा। ईरान सीरधि के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन भी कर रहा है और उसने नवनरिमति गैर-परमाणु बैलसिटिक मसिाइलों का परीक्षण भी कधि है। अमेरिका इस संबंध में एक दूसरी डील करना चाहता है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक सके।"

इसके अलावा, परमाणु डील खतम करने के पीछे इज़राइल को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। वदिति हो कि कुछ ही दनि पहले इज़राइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर आरोप लगाया था कि उसने डील की आड़ में अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा है और दुनधि को धोखे में रखा है। वहीं अमेरिका के वदिश मंत्री माइक पोपधियो ने भी कहा था कि इज़राइल ने जो बातें कही हैं, वह सटीक हैं और ईरान ने दुनधि को धोखे में रखा है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

समझौते की पृष्ठभूमि

13 साल के कूटनीतिक प्रयासों के परणामस्वरूप ईरान एवं छह प्रमुख शक्तिशाली देशों (पी5+1=अमेरिका, रूस, चीन, फ्राँस, ब्रिटिन+जर्मनी) के बीच 18 दनों तक वधिना में चली वारता के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दधि गया था।

क्या खास था समझौते में?

- ईरान अपने परमाणु केंद्रों की नगरिानी रखने पर सहमत हुआ था
- ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों की जाँच के लधि संयुक्त राष्ट्र के नरिीक्षकों को अनुमति देने पर सहमत जितार्ई थी
- ईरान को अपने कुल संवर्धति यूरेनियम का 98% हसिसा नष्ट करना था
- ईरान पर हथियार खरीदने के लधि लगाया गया प्रतर्बिध 5 वर्षों तक जारी रहना था
- ईरान 8 साल तक किसी भी तरह की मसिाइल तकनीक नहीं खरीद सकता था
- 15 साल तक ईरान परमाणु हथियार भी नहीं बना सकता था
- ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के बदले अमेरिका, यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतर्बिधों से मुक्ति मिली थी
- ईरान को तेल और गैस के कारोबार, वत्तीय लेनदेन, उड्डयन और जहाजरानी के कषेत्रों में लागू प्रतर्बिधों में ढील दी गई थी
- 100 अरब डॉलर की ज़बत संपत्तिका इस्तेमाल करने की छूट ईरान को दी गई थी

कूटनीतिक दृष्टिका अभाव

ट्रंप अक्सर ही अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा के फैसले को पलटते दधि हैं। अब तक उन्होंने बार-बार खुद को एक ऐसे नेतृत्व के रूप में ही पेश कधि है, जो न केवल समझौतों को खतम करने में नपुण है, बल्कि जसिके पास नीतिका गहरी समझ या कूटनीतिक दृष्टिका अभाव है।

- ईरान के साथ परमाणु समझौते से अलग होते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह आने वाले दिनों में कहीं बेहतर करार करने में सफल होंगे, जो ईरान की बैलस्टिक मिसाइलों और कश्मिर में उसके प्रभाव को नयित्तरति करेगा।
- कुछ ऐसा ही उन्होंने तब भी कहा था, जब उन्होंने **पेरसि जलवायु समझौते** से अमेरिका को बाहर निकाला था, लेकिन नतीजा सबके सामने है।
- अमेरिका में ओबामा केयर से कहीं बेहतर **'हेल्थकेयर'** लाने का उनका वादा भी सच नहीं चढ़ सका है।
- **'डफिरेड एकशन फॉर चाइलडहुड एराइवल्स प्रोग्राम'** को भी उन्होंने इसी प्रकार अचानक बंद कर दिया था।
- उल्लेखनीय है कि सत्ता में आते ही उन्होंने **ट्रांस-पैसफिक पार्टनरशिप** से पीछे हटने की घोषणा की थी।

ईरान पर क्या होगा प्रभाव?

- अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। प्रतबंधों के चलते ईरान को भुगतान लेने-देने में दकिकत आएगी। भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने वाले अधिकांश बैंकों पर अमेरिका का कब्जा है। ऐसे में चाहकर भी भारत जैसे बहुत से देश ईरान से तेल लेने से कतराएंगे।
- इसके अलावा उच्च जोखिम के चलते इंडोनेसिया के बनिा क्रूड का परिवहन होना असंभव हो जाता है। यह सुविधा मुहैया कराने वाली ज्यादातर कंपनियाँ अमेरिका के प्रभाव वाली हैं। ऐसे में यहाँ भी दकिकत बनी रह सकती है।
- शपिंग में अमेरिका का एकाधिकार तो नहीं है, लेकिन कहीं-न-कहीं सभी शपिंग कंपनियों के तार अमेरिका से जरूर जुड़े रहते हैं। प्रतबंध लगने के बाद ये कंपनियाँ ईरानी कच्चे तेल को लाने-ले जाने से कतराने लगेगी।

भारत पर क्या होगा इसका प्रभाव?

अमेरिका के इस कदम का दुनियाभर में प्रभाव होगा। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होगी ही पश्चिमी एशिया भी अछूता नहीं रहेगा।

नश्चिति ही भारत भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे व्यापारिक और चाबहार जैसे सामरिक हति ईरान के साथ जुड़े हैं।

भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी नविश भी किया है और वहाँ गैस फील्ड को लेकर भी बात चल रही है।

तेल व्यापार पर पड़ सकता है प्रभाव

- इराक तथा सऊदी अरब के बाद ईरान भारत के लिये तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है, जिसने 2017-18 के वित्तीय वर्ष में भारत को प्रथम 10 माह (अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2018 तक) में 18.4 मिलियन टन कच्चे तेल की आपूर्ति की।
- वदिति हो कि 2010-11 तक ईरान भारत के लिये दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतबंधों के कारण यह अपना स्थान बरकरार नहीं रख सका।
- 2013-14 तथा 2014-15 में भारत ने ईरान से क्रमशः 11 मिलियन टन तथा 10.95 मिलियन टन तेल खरीदा।
- 2015-16 में यह बढ़कर 12.7 मिलियन टन तथा 2016-17 में बढ़कर 27.2 मिलियन टन हो गया।
- अमेरिकी फ़ैसले का तात्कालिक असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इसके दाम 80 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास पहुँच गए हैं। इससे भारत का तेल आयात बलि का बढ़ना तय है।
- दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल का खरीददार है। ऐसे में अमेरिका से डील टूटने का असर भारत और ईरान के बीच तेल के व्यापार पर पड़ सकता है।
- भारत को फिर एक बार उन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो इस डील के होने से पहले मौजूद थीं।
- उल्लेखनीय है कि 2015 में इस डील के होने से पहले अमेरिका ने ईरान पर तमाम प्रतबंध लगा दिये थे, जिसके बाद भारत को ईरान से तेल की खरीददारी से हाथ खींचने पड़े थे।
- अब पहले की तरह भारत का मार्केट एक बार फिर से इराक और सऊदी अरब की ओर और अधिक शिफ्ट हो सकता है।
- ईरान भारत को गेहूँ के बदले भी क्रूड बेचने का प्रस्ताव दे चुका है।

फलिहाल अमेरिका की ओर से प्रतबंधों के बाद भारत की ओर से पहली प्रतिक्रिया यही आई है कि इस फ़ैसले का तात्कालिक कोई बड़ा प्रभाव भारत पर नहीं होगा। जब तक यूरोपीय संघ इन प्रतबंधों को लागू नहीं करता, तब तक भारत के लिये चिंता की कोई बात नहीं है। तेल के बदले भारत यूरो में ईरान को पेमेंट कर सकता है, जो उसने अतीत में किया भी है। लेकिन यदि प्रतबंधों को यूरोपीय संघ भी लागू करता है तो फिर दोनों देशों का कारोबार प्रभावित होगा।

चाबहार परियोजना प्रभावित हो सकती है

- 2015 में हुई डील के बाद ही भारत को ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिली थी।
- वदिति हो कि चीन-पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह परियोजना के जवाब में ईरान-भारत चाबहार बंदरगाह के विकास पर काम कर रहे हैं।
- चाबहार के माध्यम से भारत ने ईरान में काफी नविश कर रखा है। वह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिये ईरान के ज़रिये ही रास्ता बना रहा है।
- भारत चाबहार पर अब तक करीब 85.21 मिलियन डॉलर का नविश कर चुका है। 12.2 करोड़ डॉलर यानी 78 हजार करोड़ रुपए का नविश और करेगा। इसके अलावा 8.5 करोड़ डॉलर बंदरगाह के उपकरणों पर भी खर्च किये जाएंगे।
- भारत चाबहार बंदरगाह के विकास के लिये ईरान को 15 करोड़ डॉलर का ऋण भी दे रहा है, जिसमें से 6 अरब डॉलर की राशि जारी भी की जा चुकी है।

इसके अलावा नवीनतम परिस्थितियों भी ईरान के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित कर रही हैं, विशेषकर इज़राइल और सऊदी अरब के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकियाँ। हाल के समय में ईरान के साथ भारत के संबंधों में कुछ गरिबत आई भी है। इसकी दो बड़ी वजह हैं-- 1. ऑयल फील्ड को रूसी कंपनियों को सौंपना, 2. चाबहार परियोजना में चीन और पाकिस्तान को शामिल करने का प्रस्ताव। इन दोनों बातों से भारत की नाराज़गी बढ़ी है। ऐसे में यह देखना होगा कि भारत प्रतबंधों के बाद अमेरिका को इस परियोजना के लिये कैसे राजी करता है। इसके अलावा अमेरिका की दबाव की रणनीति भी इस दिशा में काम करेगी।

इसके साथ-साथ यदि चाबहार परियोजना धीमी होती है तो इसके परिणामस्वरूप अमेरिका के आग्रह पर शुरु की गई अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण प्रक्रिया में भारत द्वारा दी जाने वाली 1 बिलियन डॉलर की सहायता तथा 100 अन्य छोटी परियोजनाओं पर किया जाने वाला कार्य भी प्रभावित हो सकता है

ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिये अब क्या विकल्प है? आखिर इन प्रतिबंधों का कतिना असर देखने को मलिया और भारत की आगे की रणनीतिक्रिया हो सकती है? इन प्रतिबंधों का खुद ईरान पर क्या असर होगा? अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जल्दी ही जब अमेरिकी प्रतिबंधों की रूपरेखा सामने आएगी तब इन सभी सवालों के जवाब मलि जाएंगे।

क्या कहना है अन्य वैश्विक शक्तियों का?

ईरान के साथ परमाणु समझौते को खत्म करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर दुनियाभर में तीखी प्रतिक्रिया जताई गई है। ईरानी सांसदों ने संसद में कागज से बने अमेरिकी झंडे और समझौते की प्रतियों को जलाया। ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा कि ट्रंप सरिफ ताकत की भाषा समझते हैं। इसके बाद ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम फिर शुरु करने का ऐलान कर दिया है तो फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने चिंता जताते हुए समझौते के साथ बने रहने की प्रतिबद्धता जताई है। रूस और चीन का अमेरिका वरिध कसि से छपि नही है और ये दोनों कसि भी परस्थितिमें ईरान के साथ ही खड़े नज़र आएंगे।

ईरान: ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा, अमेरिकी घोषणा से जाहिर होता है कि वह अपने ही वादों का सम्मान नहीं करता। ईरान का मानना है कि यह परमाणु समझौता तभी बच सकता है, जब समझौते के अन्य साझीदार ट्रंप की उपेक्षा कर दें। उन्होंने चेतावनी भी दी कि समझौता वफिल होने पर उनका देश फरि से यूरेनियम संवर्धन करेगा।

- **रूस:** रूस ने अमेरिका के परमाणु डील से पीछे हटने को सबसे बड़ी भूल बताया है। रूस का कहना है कि इससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मलिया और यह तनाव को जन्म देगा। इस गलत फैसले से मध्य-पूर्व में युद्ध तक संभव है।
- **चीन:** चीन का कहना है कि अमेरिका के इस डील से पीछे हटने पर उसे हैरानी हुई है। चीन इस डील का समर्थन करता है। इस डील के टूटने से चीन को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
- **जर्मनी:** जर्मनी ने कहा है कि ट्रंप के फैसले के बावजूद वह इस डील से अलग नहीं होगा। जर्मन सरकार इस अहम दस्तावेज़ का समर्थन करती रहेगी, जिससे मध्य पूर्व और दुनिया में सुरक्षा बेहतर हुई है।
- **फ्रांस:** फ्रांस के राष्ट्रपति एमन्युएल मैक्रॉन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके बाद परमाणु अप्रसार व्यवस्था ढाँच पर लगी है।
- **ब्रिटेन:** ब्रिटेन का कहना है कि अमेरिका के इस डील के हटने के बाद भी वह परमाणु डील का सम्मान करेगा और इससे जुड़ा रहेगा।
- **इजराइल:** इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के फैसले की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। इजराइल यह मानता है कि ईरान न सरिफ इस डील के दरिखाने के रूप में अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखे हुए था बल्कि वह सीरिया को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा था।
- **सऊदी अरब:** परमाणु डील से अमेरिका के पीछे हटने का स्वागत करते हुए सऊदी अरब ने कहा है कि यदि उनका पड़ोसी दुश्मन परमाणु हथियार बनाएगा तो वह भी इससे पीछे नहीं हटेगा। वह भी अपनी सुरक्षा के लिये परमाणु हथियारों का निर्माण तेज़ी से करेगा।

(टीम ट्रिप्ट इनपुट)

पश्चिमी एशिया पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव

ओबामा के बाद अमेरिका को यह लगता रहा है कि यह समझौता ईरान के पक्ष में झुका हुआ है और इससे अमेरिका के हित नहीं सधते, जबकि पूर्व में लगे प्रतिबंधों से ईरान को परेशानी भी हुई और उसकी अर्थव्यवस्था भी खासी प्रभावित हुई थी। 2013 में पदग्रहण करने वाले हसन रूहानी प्रथम नरिवाचित राष्ट्रपति थे, जो आर्थिक वृद्धि बहाल करने, पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने और नागरिक अधिकारों को स्थापित करने के कार्यक्रम के आधार पर सत्ता में आए थे। अमेरिका शायद चाहता था कि ईरान प्रतिबंधों से पूरी तरह तबाह हो जाए और घुटने टेक दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिमी एशिया की राजनीति में ईरान की भूमिका जारी रही और उसने विश्व की कई शक्तियों के साथ अपने संबंधों को मज़बूती दी। अब स्थिति चाहे कोई भी रूप ग्रहण करे, लेकिन एक बात तय है कि पश्चिमी एशिया में ईरान का बहुत कुछ ढाँच पर लगा हुआ है।

नषिकरष: रूस और चीन के साथ ईरान की बढ़ती नज़दीकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बराबर खटकती रही है, इसलिये अब वह ईरान पर नए सरि से कड़े प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। वह ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जिससे अमेरिकी ताकत का इज़हार हो। भारत इस समझौते का समर्थक रहा है और उसने हमेशा यह प्रतिबद्धता जताई है कि ईरान के परमाणु मसले को वार्ता तथा कूटनीतिके द्वारा शांतपूरवक ढंग से हल किया जाना चाहिये। भारत का कहना है कि सभी संबंधित पक्षों को ईरान परमाणु समझौते से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये सक्रिय रूप से एक साथ आना चाहिये। भारत के इस कषेत्र में व्यापक हित जुड़े हैं और ईरान को लक्षित करने के लिये अमेरिकी प्रतिबंध इसके कषेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों सऊदी अरब और इजराइल के साथ मलिकर इस कषेत्र को अस्थिर कर सकते हैं, जहाँ 8 मलियन से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे में यदि भारत और ईरान का परस्पर संबंधों को स्थिर तथा मज़बूत बनाए रखने का महत्त्व तो है ही, साथ ही दोनों देशों को यह प्रयास करना होगा कि प्रतिबंधों के बावजूद संबंधों पर कोई विशेष प्रभाव न पड़े। इसके अलावा भारत को **रुपया-रियाल व्यापार प्रक्रिया** तथा दोनों देशों के बीच धन प्रवाह तथा आय को बनाए रखने के लिये भारत में ईरानी बैंकों की स्थापना जैसे विकल्पों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। बहरहाल, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप का फैसला विश्व के शक्ति संतुलन को कसि तरह प्रभावित करता है।

